इंफ्रास्ट्रक्चर को गति, पुरानी परियोजनाओं को आर्थिक शक्ति

एक्सक्लूसिव न्यूज, लखनऊ : इस वित्त वर्ष के पहले अनुपूरक बजट में योगी सरकार ने जहां इंफ्रास्ट्रक्चर को गति देने के लिए सिंचाई, सड़क, पानी, शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं पर जोर दिया है। वहीं प्रदेश में केंद्र की तरह ये पता ही योजनाओं को रफ्तार देने की कोशिश भी की है, ताकि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले इन योजनाओं को जमीन स्तर पर पूरा किया जा सके। अनुपूरक में पिछले वित्तीय वर्ष के बजट : से 13 तक के बाकी को मंजूरी और अगली बजटों के बाद में 30 करोड़, राजकीय मंजूरी, मुख्य प्रतियोगी के लिए 330 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि का प्रावधान है। राजकीय मेडिकल कॉलेजों के लिए 474 करोड़ रुपये, राजकीय मेडिकल कॉलेजों के कर्मचारियों और छात्रों के वेतन के लिए 174 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

केंद्र की योजनाओं को मिलेगी रफ्तार : केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत शौचालय निर्माण के लिए 1,523 करोड़ और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए 110 करोड़ रुपये दिए गए हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना

शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क... सभी का अनुपूरक में रखा गया ध्यान

निजी स्कूलों में मिल सकेगी अच्छी शिक्षा

गरीबों के बच्चों को बढ़िया स्कूलों में पढ़ने के लिए पैसे की कमी न होने पाये, इसके लिए अनुपूरक के बजट 268 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त करने के लिए केंद्र की पोषण योजना में भी अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था की गई है। इस योजना के तहत 160 करोड़ रुपये का आवंटन होगा। राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में इंफ्रास्ट्रक्चर और नए निर्माण के लिए 353 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। माध्यमिक परीक्षा कराने के लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर होने वाले खेलों में ज्यादा से ज्यादा स्कूली बच्चे शामिल हों, इसके लिए 185 करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। आईटीआई के छात्र-छात्राओं को स्कॉलरशिप और स्नातकोत्तर कक्षा के निर्माण के लिए 92 करोड़ रुपये और छात्रा आवासीय विद्यालयों की स्थापना के लिए 54.48 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

सड़क और पुलों का जाल

प्रदेश में सड़क और पुलों के निर्माण व उनके रखरखाव के लिए 4250 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। सड़क और पुलिया की मरम्मत के लिए 300 करोड़ रुपये, ग्राम सड़क निधि के अर्जित सड़कों के अनुरक्षण के लिए 250 करोड़, औद्योगिक और लॉजिस्टिक पार्क में 4 लेन सड़क के लिए 250 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। नए जिला मार्ग के लिए 105 करोड़ और खराब रोडों में पुलों के निर्माण के लिए 30 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

राज्य राजधानी क्षेत्र की राह सुगम

राजधानी लखनऊ सहित छह जिलों को मिलाकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र (एसकीआर) विकसित करने की योजना को एक ठोस रूप देने। अनुपूरक में इसके लिए 50 करोड़ की व्यवस्था है। वहीं, हजरतगंज में ऑलिंपिक तौर पर पार्किंग विकास के एकीकृत प्लान के लिए भी पैसा दिया गया है। लखनऊ में मुंबई इन्फ्रास्ट्रक्चर आवाजाही के साथ-साथ राज्य स्तर विकास चलने के साथ ही उसके लिए बजट का इंतजाम भी कर दिया गया है।

विकास व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 1,530 करोड़, विकास प्राधिकरणों को मजबूत करने के लिए 1,226 करोड़, विकास योजनाओं को चलाने के लिए 3,230 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

के क्रियान्वयन के लिए 65 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। राजकीय इकाइयों में पेयजल पहुंच सुधार बढ़ाने के लिए 700 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

सड़क ब्रिज के क्रियान्वयन पूर्वांचल योजना तेज : पूर्वांचल के अलग-अलग जनपदों के लिए 464 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। महिला अपराधों पर लगाम लगाने के लिए 66 नए थानों में 66 लाख रुपये से महिला हेल्प डेस्क बनाई जाएंगी। सड़क ब्रिज हेल्पलाइन 1090 के क्रियान्वयन के लिए 54 लाख का प्रावधान है।

तीन फास्ट एक्सप्रेस को सुपर डोज : प्रदेश में तीन नए फास्ट एक्सप्रेस शुरू हो जाएं, इसके लिए अनुपूरक में 325 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। लखनऊ में मिलेनियम

इन परियोजनाओं पर फोकस

- किसानों को सम्मान योजना के लिए ₹20 करोड़
- लखनऊ-हरदोई के बीच बनने वाले टेक्सटाइल पार्क के लिए ₹5 करोड़
- खाद्य प्रसंस्करण नीति के क्रियान्वयन के लिए ₹54 करोड़
- मां-सरकार केंद्रों की स्थापना के लिए ₹10 करोड़
- पूर्वांचल में सीवेज निपटान निधि के लिए ₹300 करोड़, बुंदेलखंड के लिए ₹75 करोड़
- नई सोलोजन बसों की खरीद के लिए ₹100 करोड़
- पर्यटन स्थलों के विकास के लिए ₹110 करोड़
- मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए ₹200 करोड़

जगी कर्मचारियों की आस

- राज्य कृषि फीफर के रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए ₹50 लाख
- पैरामेडिकल कर्मचारियों के वेतन के लिए ₹50 करोड़
- राजकीय होम्योपैथिक डिस्पेंसरियों, होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजों के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए ₹11 करोड़
- पॉलिटेक्निक के गेस्ट लेक्चरर के मद में ₹2 करोड़
- उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा, उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों के वेतन, सैलरी के मद में ₹6.67 करोड़
- शिक्षकों के जनपदीय समायोजन नियम तथा विधि के वेतन-भत्तों के लिए ₹1 करोड़
- जीएसटी कर अधिकारियों के वेतन के लिए 3.52 करोड़

...ताकि मिले अच्छी शिक्षा

- मेरठ, अलीगढ़, इटावा के सैनिक स्कूलों के छात्र-छात्राओं की स्कॉलरशिप के लिए ₹20 करोड़
- गोरखपुर सैनिक स्कूल के निर्माण के लिए ₹5 करोड़
- NCC परिसर अलाहाबाद, गोरखपुर की स्थापना के लिए ₹12 करोड़
- गोरखपुर और लखनऊ में केंद्रीय विद्यालयों के लिए ₹12.71 करोड़
- 11 नए राजकीय संस्कृत माध्यमिक विद्यालय, 100 बेडेड छात्रावास के 5 नए संस्कृत माध्यमिक विद्यालय की स्थापना के लिए ₹5 करोड़
- गोरखपुर में मुख्यमंत्री विद्यालय के लिए ₹2 करोड़
- सर्व शिक्षा अभियान के मद में ₹233 करोड़